The Trivandrum Gulf sector is the monopoly of Air India. It is charging Rs. 2800/- as air fare between Dubai-Trivandrum whereas the air fare between Dubai and Delhi *via* Bombay is only Rs. 1800 although the distance between Dubai and Delhi is more than that between Dubai and Trivandrum. The other air lines are charging much less for the same distance.

The Malayalees working in the Gulf countries have made repeated representations urging upon the Government to reduce the high fare. So far no action has been taken by the Government. It must be remembered that these people who are working in these countries are bringing us valuable foreign exchange. 85% of the people working in Gulf countries are labourers and it is unfortunate that a State agency should exploit them to this extent. It is also reported that their baggage is also weighed and anything weighing more than 20 kgs. is charged by Air India. No other airline resorts to this practice.

It is reported that because of this attitude of the Air India the Association of the Gulf Malayalees has decided to boycott Air India.

Therefore, I would request the Government to immediately take steps to reduce the air fare in the Gulf-Trivandrum sector and afford the necessary relief to the Gulf Malayalees.

(v) Demand for Central Government's taking action in the matter of authorities not having allowed a Conference of Harijans and Tribals scheduled to be held in Patna on 9th October, 1983.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अक्तूबर, 1983 को बिहार राज्य हरिजन आदिवासी सम्मेलन पटना, गांधी मैदान में था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री शिबू सोरेन, एम०पी० थे, अध्यक्ष श्री एन०ई० होरो, सांसद थे तथा उद्घाटन मैंने किया था। सम्मेलन में श्री कुलेन्दुबेलू, एम. पी. के अलावा देश के विभिन्न भागों से प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बीच सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक चेतना लाना तथा आत्म-सम्मान की भावना पैदा करना था। सम्मेलन में आठ द्वार बनाए गए थे। सम्मेलन-स्थल एवं श्री कृष्ण मेमोरियल हाल का रिजर्वेशन तीन माह पहले करा दिया गया था। लेकिन 8 अक्तूबर को जब मंच बन कर तैयार हो गया और गेट एवं टेन्ट वगैरह गाड़ दिए गए तो जिलाधिकारी के आदेश से मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने मंच को तोड़ डाला, टेन्ट को उखाड़ फेंका और गेट को उखाड़ कर ले गये। श्री कृष्ण मेमोरियल हाल तीन माह पहले रिजर्व किया गया था और उसका पैसा जमा कर दिया गया था, लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि अधिकारी सवेरे से ही उस पर ताला लगा कर गायब हो गये और रात तक गेट नहीं खुला।

अत: केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि चूंकि अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की भलाई एवं सुरक्षा का मामला केन्द्र से भी सम्बन्धित है, इसलिये केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाई करे।

सेठी साहब, मैंने आपको भी लिखा है, मैं समझता हूं आप इस पर एन्क्वायरी कराएंगे।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैंने मुख्य मंत्री को लिख दिया है।

(vi) Need for Government's intervention to stop action on Vice-Chancellor's order for deduction of 30 percent marks of all graduate and post-graduate examinees on account of copying in certain colleges affiliated to Gorakhpur University.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान गोरखपुर विश्वविद्यालय

से सम्बद्ध महाविद्यालयों के उन समस्त छात्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां समस्त ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के छात्रों के 30 प्रतिशत अंक कम करने की घोषणा विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा की गई है। कहा जाता है कि यह घोषणा इस कारण की गई है कि कुछ कालेजों में छात्र नकल करते हुए और कुछ में सामूहिक रूप से नकल करते हुए पकड़े गये थे।

इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 103 महाविद्यालय हैं जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हजारों की संख्या में छात्र हैं। जिन छात्रों ने गलती की है उन्हें उनकी गलती की सजा मिले, इसमें छात्रों, छात्र संगठनों अथवा अन्य किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अधिसंख्य नकल के विरूद्ध हैं। किन्तु उपकुलपति द्वारा इतना कठोर निर्णय लेना और गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कालेजों के सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों में से 30 प्रतिशत अंक कम कर देना न तो न्यायसंगत है और न तर्कसंगत। मेरी जानकारी में अनेकों ऐसे कालेज हैं जिनमें नाम मात्र को नकल नहीं हुई। वहां के व्यवस्थापक नकल होने देना पसन्द नहीं करते।

उपकुलपति की इस कार्यवाही के प्रति छात्रों एवं उनके संरक्षकों में व्यापक असंतोष है, वे आन्दोलित हो रहे हैं और निकट भविष्य में इस रोष की बुरी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। मेरा सुझाव है सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप करे और सामूहिक रूप से छात्रों के प्राप्तांकों में से नम्बर काटने की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है उसे रोका जाय और इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जायें, क्योंकि इन सब विश्वविद्यालयों को यू०जी०सी० ग्रान्ट देती है। अतः केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह यह देखे कि ये विश्वविद्यालय ठीक प्रकार से चल रहे हैं।

(vii) Need to Direct Public Financial Institutions not to support proposed merger of Indian Aluminium Company with Mahindra & Mahindra Co.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : I raise under Rule 377 the following matter of urgent public importance.

The proposed merger of Indian Aluminium Co. (Indal) with Mahindra & Mahindra Co. (M & M) is pending before the Government of India for their approval. It is reported that the public financial institutions have no objection to the proposed merger.

But, in our opinion, this amalgamation will be against the national interest. It has been opposed by the workers and the staff of the Indal and their unions, and is resented by a large number of small and medium shareholders of Indal.

It will allow a giant multinational company (Alcan Aluminium Ltd., Canada) to widen its scope of operation and enter into more lucrative sectors of agricultural tractors and automobiles which supply jeeps to the Defence Department.

Alcan, Canada, presently 50% equity holders in Indal, is interested in the amalgamation since repatriation of dividends from India will increase after merger. FERA regulations will no longer apply to them as they will hold 28% equity in the merged company. But in reality they will hold sway over both the aluminium and the automobile division of the merged company as they will be the single biggest equity holder after public financial institutions. M & M's share will be only 0.75%. So, under the guise of 'Indianisation' it is a move by a large foreign monopoly house to get around FERA restrictions.

Therefore, we request the Government